

रजिस्टर्ड नं० एल०-३३/एस०-एम०/१३-१४/९९.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, १४ जनवरी, २०००/२४ पौष, १९२१

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-२, १४ जनवरी, २०००

संख्या एल० एल० आर०-डी (६)-२०/९९-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के अनुच्छेद २०० के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक १२-०१-२००० को अनुमोदित मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, १९९९ (१९९९ का विधेयक संख्यांक १८) को २००० के हिमाचल प्रदेश

अधिनियम, संख्यांक 1 के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा;

रामेश्वर शर्मा,
सचिव (विधि)।

2000 का अधिनियम संख्यांक 1.

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 1999

(राज्यपाल द्वारा तारीख 12-1-2000 को यथा अनुमोदित)

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 1999 है । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(2) यह नवम्बर, 1999 के प्रथम दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

1971 का 3

2. मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन ।

(क) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(क क) “लाइसेंस फीस” से, इस अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार, मंत्री को आबंटित सुसज्जित गृह के बारे में संदेय मासिक धन-राशि अभिप्रेत है ;” ; और

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) “वेतन” से, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन मंत्री को संदत्त मासिक वेतन अभिप्रेत है ।” ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

धारा 4 का संशोधन ।

(क) “निःशुल्क” शब्द जहाँ कहीं भी यह आता है, का लोप किया जाएगा ; और

(ख) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) प्रत्येक मंत्री, उसे आबंटित सुसज्जित गृह के बारे में, अपने वेतन के 10 प्रतिशत की दर से लाइसेंस फीस संदत्त करने का दायी होगा और वह प्रतिमास उसके वेतन से वसूली होगी ।” ।

4. मूल अधिनियम की धारा 9-क में, “निःशुल्क” शब्द का लोप किया जाएगा । धारा 9-क का संशोधन ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 1 of 2000.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT ACT, 1999

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 12TH JANUARY, 2000)

AN

ACT

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title
and
commence-
ment.

1. (1) This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1999.

Amendment
of section 2.

2. In section 2 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act),—

(a) after clause (a), the following clause shall be added, namely:—

“(aa) “licence fee” means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of section 4 of this Act in respect of a furnished house allotted to a Minister ;” ; and

(b) after clause (c), the following clause shall be added, namely:—

“(d) “salary” means the monthly salary paid to a Minister under section 3 of this Act.”.

Amendment
of section 4.

3. In section 4 of the principal Act,—

(a) the word “free”, wherever it occurs, shall be deleted ; and

(b) after sub-section (2), the following sub-section shall be added, namely:—

“(3) Each Minister shall be liable to pay licence fee @ 10% of his salary in respect of the furnished house allotted to him and the same shall be recoverable monthly from his salary.”.

Amendment
of section
9-A

4. In section 9-A of the principal Act, the word “free” shall be deleted.